सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-30 अंक-7 7 से 21 अप्रैल, 2015 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com मूल्य : 2 रुपये

क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं का काम करने का ढंग कैसा हो

— शिवदास घोष

24 अप्रैल, 2015 को हमारी प्रिय पार्टी एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) का 68वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हमारे प्रिय नेता, शिक्षक और पथप्रदर्शक इस युग के अन्यतम मार्क्सवादी चिन्तनकार कॉमरेड शिवदास घोष की कृति ''क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं का काम करने का ढंग कैसा हो'' (कलैक्टिव वर्क्स, खण्ड 4, अंग्रेजी से अनुदित) की पहली किश्त को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। कॉमरेड घोष की यह अमूल्य चर्चा वर्तमान स्थिति में अपने क्रान्तिकारी चरित्र का निर्माण करने और विश्व साम्राज्यवाद तथा भारतीय पूँजीवाद के खिलाफ जन आन्दोलन गठित करने के लिए जरूरी सांगठनिक तैयारी में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेगी।

कॉमरेड्स,

आज पार्टी संगठन के लगभग सभी स्तरों पर दृष्टिगोचर हो रही प्रमुख कमजोरियों को दूर करने के सवाल पर ही मुख्यत: चर्चा करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी की यह विस्तारित बैठक बुलाई गई है। पार्टी निर्माण करने के संघर्ष के इतिहास में एक नाजुक समय पर ये कमजोरियाँ उजागर हो रही हैं। हमारी विरोधी ताकतों के वैमनस्यपूर्ण व्यवहार और हमें एक तरफ धकेल देने के उनके इरादे के राजनीतिक महत्त्व को यदि हम ठीक से समझें और इससे उत्पन्न मुश्किलों से यदि परेशान नहीं हों, तो यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि हमारे बुरे दिन चल रहे हैं। घोर रुकावटें और मुश्किलें हैं, लेकिन पार्टी की साख बढ़ रही है, हमारी राजनीतिक लाइन के बारे में, हमारी पार्टी की भविष्य में संभावनाओं और इसके फैलाव की गुंजाइश के बारे में जनमानस में रुचि भी तो बढ़ रही है। यदि हम इन तमाम बातों को ठीक से समझ लें, तो आसानी से देख सकते हैं कि हमारे फैलाव और विकास के लिए यह एक शानदार अवसर है, जो पार्टी इतिहास में पहले कभी नहीं आया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि हम इस परिस्थिति के अवसरों का ठीक से फायदा उठा सकें, तो तमाम अतीत के मुकाबले सापेक्षत: स्थिति हमारे सर्वाधिक अनुकूल है। लेकिन उपयुक्त समय का मतलब यह नहीं है, कि अब विरोध कम है। इसका मायने है कि यदि पार्टी कार्यकर्ता सभी स्तरों पर हमलों और दिक्क्तों का राजनीतिक तौर पर मुकाबला करने की शक्ति, क्षमता और राजनीतिक चेतना व परिपक्वता हासिल कर सकें और यदि वे सही तरीके से पार्टी बॉडियों और जन संगठनों की कमेटियों का गठन कर सकें तो वर्तमान समय हमारे फैलाव व विकास के लिए निश्चित ही बहुत शानदार है। क्योंकि लोग हमें सुनना चाहते हैं और हमारे प्रति अच्छी भावना रखते हैं। सिर्फ आम जनता के बीच ही नहीं, हमारी पार्टी के प्रति घोर विरोध के बावजूद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की पार्टी-पांति में भी एस.यू.सी.आई.(सी) की राजनीति का परोक्ष व अपरोक्ष प्रभाव विभिन्न प्रकार से महसूस किया जा सकता है। इसकी पुष्टि अनेक लक्षणों से होती है।

इसलिए ऐसे एक समय में हमारी पार्टी-पांति को और भी एकताबद्ध होना चाहिए। प्रत्येक कार्यकर्ता को राजनीतिक पहलकदमी व राजनीतिक चेतना को बढ़ाना होगा। राजनीतिक पहलकदमी लेने की क्षमता और राजनीतिक कार्यकलापों तथा सम्पूर्ण रूप से सामूहिक कार्य पद्धति व शैली को उन्नत करना होगा–समय की मांग को पूरा करने के लिए इन सभी को सुधारना होगा। अब यही है मुख्य कार्य। हमारे कार्य की गति को बढ़ाने के सवाल को ध्यान में रखते हुए, मैं उन बातों पर चर्चा करना चाहूँगा जिन्हें सभी स्तरों पर पूरा करना है। आप सभी को, विशेषकर अगुआ कॉमरेडों को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता को अपनी राजनीतिक पहलकदमी बढ़ाने और अपनी राजनीतिक चेतना के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि रोजमर्रा के जीवन और राजनीतिक आन्दोलनों में विभिन्न कामों को पूरा करने और जिम्मेदारियों को निभाने में उसकी निजी राजनीतिक व संगठनात्मक पहलकदमी को और भी विकसित किया जा सके। इसके मायने हैं हर समय नेताओं से निर्देश मिलने का इंतजार नहीं करना है कि क्या करें? ऐसा नजरिया नहीं होना चाहिए कि जब निर्देश आएगा तब ही हम में से प्रत्येक उसको बेहतरीन तरीके से लागू करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा; उस समय भी जब कोई निर्देश नहीं आता है, हम में से प्रत्येक अपने काम करने की योजना उपयुक्त ढंग से बनाएगा। इसका मतलब है कि यदि कोई सवाल उठ खड़ा हो तो कॉमरेड उसका उत्तर देने का खुद प्रयास करें और इसके लिए हर बार उन्हें नेतृत्व के पास दौड़ना नहीं पड़े। ऐसा करने के प्रयास में वे गलती कर सकते हैं लेकिन तब वे इनसे सीख लेंगे, गलतियों को बता कर कोई उनकी मदद करेगा। हर कोई अपने को इसी प्रकार तैयार करेगा। एक सवाल को पहले खुद जांचने की बजाय जवाब जानने के लिए नेतृत्व के पास दौड़ने की मौजूदा आदत या जब भी कोई नाजुक सवाल खड़ा हो जाए तो हतप्रभ हो जाना–ये कार्यकर्ताओं की चेतना में कमी के लक्षण हैं और इस बात को इंगित करते हैं कि हम कार्यकर्ताओं को सही ढंग से तैयार नहीं कर पाये हैं। दूसरे, सामूहिक तौर से काम करने का अभ्यास जो हमारी पार्टी में जारी है, इसके तरीके को और भी सुधारने की जरूरत है, ताकि प्रत्येक कॉमरेड की निजी पहलकदमी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

काले कानून 'गुजरात कण्ट्रोल ऑफ आर्गेनाईज़्ड क्राईम' बिल का एसयूसीआई(सी) ने किया कड़ा विरोध

एसयूसीआई(सी) महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने निम्नलिखित बयान जारी किया:

जब यूएपीए, पीओटीए (पोटा) और एएफएसपीए (अफस्पा) जैसे मौजूदा काले कानूनों को रद्द करने के लिए लोग निरन्तर मांग करते आ रहे हैं, ये कानून नागरिकों के मूलभूत मानव अधिकारों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन करते हैं और संवैधानिक बचावों और राहतों तक पहुँच को नकारते हैं, तब बीजेपी-नीत गुजरात सरकार एक नया काला कानून गुजरात कंट्रोल ऑफ आर्गेनाइज़्ड क्राइम बिल (जीयूजेसीओसी) लाई है जो सरकार-पुलिस-प्रशासन को बेलगाम और निरंकुश शक्ति प्रदान करता है जिसमें किसी भी व्यक्ति की फोन कॉलों को सुना जा सकता है, पुलिस के सामने अपराध स्वीकारोक्ति को अदालत में मान्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य करना और बिना चार्ज के हिरासत की अवधि को 180 दिनों तक बढ़ाना शामिल है। कानून में प्रावधान है कि इस कानून के तहत अपराध गैर-जमानती होंगे और यह ''सद्भाव'' के अस्पष्ट विचार की आड़ में राज्य सरकार को कानूनी कार्रवाई से छूट प्रदान करता है। हालांकि सरकार अपराधों को बढ़ने से रोकने के लिए तथा आतंकवाद के संगठित सिण्डिकेट की गतिविधियों का दमन करने के लिए कानून का इस्तेमाल करने की बात कह रही है लेकिन लोग अपने तजुर्बे से जानते हैं कि जहाँ अपराधी और आतंकवादी किसी भी अभियोग को बेखौफ धता बताते रहेंगे वहीं कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ और बेरहम पूँजीवादी दमन के खिलाफ उठने वाली प्रतिवाद की जायज आवाज को कुचलने के लिए किया जाएगा। और एक बार गुजरात में लागू होने के बाद दूसरे राज्यों के साथ-साथ केन्द्रीय स्तर पर भी ऐसा ही फासीवादी कानून लागू किया जाना सिर्फ समय की बात रह जाएगी।

इस अति क्रूर कानून का हम विरोध करते हैं और गुजरात के ही नहीं बल्कि पूरे देश के सही सोच रखने वाले जनवाद पसंद लोगों का हम आह्वान करते हैं कि वे प्रतिवाद में उठ खड़े हों ताकि सशक्त संयुक्त आन्दोलन के दबाव के तहत सरकार को यह कानून वापस लेने के लिए बाध्य किया जा सके।

क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं का काम!!

(पृष्ठ 1 का शेष)

और भी ज्यादा बढ़ायी जा सके। हमारे सामने जो जिम्मेदारियाँ हैं, उनके मद्देनजर काम में गति हासिल करने के उद्देश्य से हमारे काम करने के तरीके में सुधार की जरूरत है और सामूहिक बॉडी संचालन व व्यक्तिगत पहलकदमी, दोनों को ही और भी बढ़ाने के तरीके लागू करने चाहिएं। मैं नहीं जानता कि दूसरे नेतागण इसके बारे में कितना सोचते हैं, लेकिन मैं तो इसके बारे में बहुत सोचता हूँ। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि हम जरूरत से बहुत पीछे हैं। भारत जैसे विशाल देश में अभी भी हम एक छोटी शक्ति हैं। इस स्थिति में हम चाहें या ना चाहें एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी हम पर आयद है। या तो इस जिम्मेदारी को हम नकार दें और इससे बचते हुए इतिहास के सामने अपने को नपुंसक साबित कर दें और नहीं तो क्रान्तिकारियों की तरह हमें इस चुनौती को मर्दानगी से स्वीकारना है और जो जिम्मेदारी हम पर आयद हुई है, उसे निभाना है। लेकिन सिर्फ सोचना और योजनाएं बनाना कि यह करेंगे, वह करेंगे काफी नहीं होगा। किसी भी कार्य को प्रभावशाली ढंग से करने का मायने है कि इसको एक आन्दोलन की तरह लिया जाए जिसमें प्रारंभिक आधारभूत काम, जरूरी तैयारी और संगठन के सभी स्तरों में संचारित होने वाली व्यापक पहलकदमी शामिल है। व्यक्तिगत तौर पर हम में से प्रत्येक को अपने आप से पूछना होगा: ''क्या मैं, अपने आप को पर्याप्त रूप से राजनैतिक तौर पर लैस कर रहा हूँ, क्या मैं किसी भी सवाल पर अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम हूँ और चाहे जिस ढंग से भी हो, किसी से पूर्व सलाह-मशविरा किए बिना ही उनको रख सकता हूँ; क्या किसी पार्टी बॉडी में चर्चा के दौरान मैं कोई सुझाव रख सकता हूँ, क्या मैं सिर्फ विचार की खातिर विचार नहीं बल्कि काम को सुधारने और मदद करने के लिए अपने विचार पेश कर सकता हूँ या सिर्फ नेताओं को सुनने और मुझे क्या करना है, उनसे यह पूछने के लिए ही मैं मीटिंग में भाग लेता हूँ?'' प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता को इसी प्रकार अपने को जांचना चाहिए और इसके अनुरूप ही अपने को ऊँचा उठाने का संघर्ष करना चाहिए। अपने आप को कैसे ऊँचा उठाएं? इसका तरीका है लोगों, पार्टी कॉमरेडों और दूसरे मित्रों के साथ हमेशा अपने को राजनीतिक चर्चाओं में संलग्न करना, मामूली मुद्दों पर चर्चा को भी अपनी राजनीति के साथ जोड़ने की क्षमता अर्जित करना। चर्चा चाहे किसी मामूली मुद्दे पर, साहित्य पर, या हंसी मजाक, रुचि के सवाल पर, सिनेमा पर या किसी चुटकुले के बारे में हो, हमें इसे चर्चा में शामिल हो जाने के लिए सूत्र बना लेना चाहिए और इसे अपनी राजनीति से जोड़ देना चाहिए ताकि चर्चा उद्देश्यपूर्ण हो जाए-रूखाई से या यांत्रिक तौर से नहीं बल्कि इस प्रकार से कि चर्चा वास्तव में ही जीवन्त हो उठे। प्रत्येक कॉमरेड को यह क्षमता अर्जित करने के लिए अपने को तत्परता से तैयार करना होगा। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि 'ओह, यह तो मात्र एक कहानी है', क्योंकि कहानी में भी संस्कृति प्रतिबिम्बित होती है। चाहे हम इस बारे में सोचे हों या नहीं, कहानी के माध्यम से भी संस्कृति लोगों को प्रभावित करती है। यहाँ तक कि हंसी-मजाक भी एक सांस्कृतिक स्तर को प्रतिबिम्बित करता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार गपशप या मजाक को भी हल्के-फुल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। जो भी मुद्दा उठ खड़ा हो या जो भी गपशप या हंसी मजाक हो, हमें इसे तुरंत अपनी मूल लाइन और पार्टी की राजनीतिक सोच के साथ जोड़ देना होगा। यह मूल लाइन हमें क्या करने को कहती है? यह लोगों के बीच पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति की भावना उभारने, जनता के बीच पूँजीवाद और इसके साथ जुड़ा जो कुछ भी है, उसके खिलाफ सही मूल्यांकन के आधार पर नफरत उभारने की जिम्मेदारी हम पर आयद करती है। मेरा मतलब अंधी नफरत से नहीं है क्योंकि उससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। काम है सही मूल्यांकन के आधार पर उन पहलुओं के खिलाफ नफरत उभारना जो ऐतिहासिक तौर से निश्शेष और नुकसानदायक हो गए हैं। हमें अपने आप को इस प्रकार तैयार करना है कि सही मूल्यांकन के आधार पर हम उन तमाम चीजों के खिलाफ नफरत उभार सकें जो आज निश्शेष और हानिकारक हो गई हैं, इसके बारे में कोई भी आकर्षण या भ्रम जिसे किसी भी जामे में खुले या छिपे तौर से पोषित किया जा रहा हो उसको तर्क और वैज्ञानिक विचार की तेज धार से पूर्णतः परास्त कर सकें और धज्जियाँ उड़ा सकें।

पूँजीवाद-विरोधी क्रान्ति की अपनी मूल लाइन के साथ किसी भी मुद्दे को जोड़ना व इसके अनुरूप ही उस लाइन की व्याख्या करना और लोगों को नकली क्रान्तिकारी ताकतों के प्रभाव से मुक्त करना, जिनकी छवि भ्रम पैदा करती है तथा पूँजीवाद-विरोधी क्रान्ति के मार्ग को अवरुद्ध करती है- ये हैं, हमारे सामने काम। ये ताकतें जिस भी क्षेत्र में जो कुछ प्रभाव रखती हैं, इनके खिलाफ ही मुख्य प्रहार की दिशा संचालित करनी होगी। यहाँ तक कि जहाँ सतही तौर पर दिखाई दे कि उनके एक विशेष स्टैण्ड या उनके द्वारा संचालित विशेष आन्दोलन में जाहिरा तौर पर कोई दोष नहीं है, वहाँ उनकी मूल राजनीतिक लाइन के साथ जोड़ कर दिखाना होगा कि वे ऐसे स्टैण्ड के माध्यम से किस प्रकार अपने फायदे के लिए झूठी छवि पैदा कर रहे हैं, जबकि उनकी राजनीतिक लाइन गलत है और किस वजह से उन्हें यह खास तरीका अपनाना पड़ रहा है। एक समय में उनके कार्यकलाप और नारे जाहिरा तौर पर हमारे जैसे ही दिखाई दे सकते हैं लेकिन हमारी स्थिति और उनकी स्थिति के बीच के बुनियादी फर्क का लोगों के सामने खुलासा करना होगा। हमारा मुख्य लक्ष्य है बुर्जुआ वर्ग को उखाड़ फेंकना और इसके साथ सामंतवाद के जो भी बचे हुए अवशेष हैं उनको भी समाप्त करना। एक विशेष नारा या एक विशेष कार्यक्रम एक ही तरह का हो सकता है, लेकिन उनके उद्देश्य भिन्न हैं। बुर्जुआ वर्ग की राजनीतिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए लगातार चर्चाओं के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को मूल राजनीतिक समझदारी के मौलिक सिद्धांतों और पूँजीवाद-विरोधी क्रान्ति के मानसिक गठन को अर्जित करना होगा। दमन के खिलाफ जनप्रिय स्टाइल में मात्र भावुक भाषणों से काम नहीं चलेगा। क्योंकि लोग खुद आमतौर पर दमन के बारे में समझते हैं। भूख के दर्द को महसूस करते हैं और दमन के खिलाफ संघर्ष की चाह रखते हैं। लेकिन वही आदमी जो पूँजीवाद के खिलाफ लड़ना चाहता है अगले ही क्षण किसी दूसरे मुद्दे पर ऐसा दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित कर सकता है जो पूँजीवाद को जारी रखने में सहायक हो। इसलिए जिन बातों की जरूरत है वे हैं पूँजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए चौतरफा संघर्ष की खातिर मानसिक तैयारी, पूरे सैद्धान्तिक-सांस्कृतिक परिमण्डल को पूँजीवाद-विरोधी दिशा प्रदान करने के जरूरी प्रयास और इस उद्देश्य के लिए अपने आप को पर्याप्त रूप से विकसित करना, ताकि प्रत्येक चर्चा और बातचीत को हम प्रभावशाली ढंग से संचालित कर सकें।

इस प्रकार अपने को विकसित करने के लिए हमें लोगों के बीच चौबीसों घण्टे काम करना होगा। इसके मायने यह नहीं है कि हम खाने और दैनिक कार्यकलाप के लिए समय नहीं देंगे या दोस्ताना गपशप में शरीक नहीं होंगे या जो प्यार करते हैं कभी-कभार एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ये तो रहेंगे ही लेकिन हमारे मन को आच्छादित नहीं करेंगे। कभी-कभी यह होगा ही, यह वास्तविक है, इसके उलट सोचना कोरी कल्पना होगी लेकिन यही मुख्य सरोकार नहीं बन जाना चाहिए। जब हम अकेले हैं या कहिए कि हो सकता है हम नहा रहे हैं, बैठे हैं या आराम करने के लिए लेटे हैं-जो बातें हम पर हावी रहेंगी और लगातार हमारे दिमाग में छाई रहेंगी-वे हैं हमारी राजनीतिक और सांगठनिक समस्याएं। परेशान कर देने वाले बहुत से मुद्दे हैं, अनेक विरोधी नजरिए और विकृतियाँ हैं। इसलिए चाहे जो भी माहौल हो, हमारा एकमात्र सरोकार होगा कि कैसे इनका समाधान किया जाए। जो कांग्रेस का मुकाबला करना चाहते हैं, उनमें सी.पी.आई. और सी.पी.आई.(एम) के बारे में कुछ भ्रम हैं; सी.पी.आई.(एम) जो सी.पी.आई. को संशोधनवादी कहती है, खुद दूसरे प्रकार का संशोधनवाद लागू कर रही है; नक्सलवादी जो सी.पी.आई.(एम) को संशोधनवादी कहते हैं, पैटी बुर्जुआ दुस्साहसिकता के माध्यम से एक दूसरे प्रकार की भ्रान्ति खुद पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार जो एक विशेष भ्रम का विरोध करते हैं, एक भ्रम को दूसरे के साथ गड्डमड्ड करते हुए अपने अन्दर अनेक भ्रम छिपाए हो सकते हैं। एक क्रान्तिकारी पार्टी भ्रमों के इस गड्डमड्ड का स्तर दर स्तर अध्ययन करती है, क्रान्तिकारी कार्यकर्ता लगातार सही राजनीति को लागू करने के माध्यम से इनका अध्ययन करते हैं और जनता को इन भ्रान्तियों से मुक्त करने के तरीके और रास्ते निकालते हैं। वे इसको कैसे करते हैं? वे इसको आपस में अपने अन्दर या जनता के बीच से उठने वाले सवालों या विषयों पर होने वाली चर्चाओं को पार्टी की मूल राजनीतिक लाइन के साथ जोड़ने के माध्यम से करते हैं। क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं का नजरिया होना चाहिए कि चर्चा में व्यवधान डालने का कोई कितना ही प्रयास क्यों न करे, मैं बातचीत में हिस्सा लूँगा और ऐसे एक बुद्धिमत्तापूर्ण व सजीव ढंग से उसके मानसिक गतिरोध को दूर करते हुए उसे मुख्य राजनीतिक चर्चा में शामिल करा लूँगा कि चाह कर भी वह पीछे नहीं हट सकेगा और अक्सर यह भी नहीं समझ पाएगा कि किस प्रकार वह अनजाने में ही दूसरी तरह की चर्चा में शरीक हो गया है। एक आदमी ने एक चुटकुला सुनाना चाहा लेकिन इसमें शामिल हो कर मैंने बातचीत शुरू कर दी जिसके चलते अनजाने में ही वह गम्भीर चर्चा में शामिल हो गया। हमें अपने आप को इस प्रकार तैयार करना पड़ता है कि हम इस राजनीतिक प्रयोजनीयता और राजनीतिक उद्देश्य से लगातार संचालित होते रहें। अकेले में चिन्तन से इसे हासिल नहीं किया जा सकता है। यह क्षमता अर्जित करने के लिए, प्रत्येक कार्यकर्ता को सुनियोजित तरीके से लगातार जनसंपर्क कायम करना होगा। इस उद्देश्य के लिए काम के निश्चित कार्यक्रम लेने होंगे तथा विभिन्न प्रकार से लोगों के बीच राजनीति को ले जाना होगा। जनता के बीच अपनी राजनीति को ले जाना होगा। अपनी राजनीति को जनता के बीच ले जाने के लिए हमें लोगों की न्यायसंगत मांगों के लिए आन्दोलन गठित करने होंगे।

यह सब करते हुए साथ ही साथ हमें दूसरों की राजनीति का मुकाबला भी करना होगा। दूसरों की राजनीति का मुकाबला सामान्य रूप से नहीं बल्कि विशेष रूप से नकली क्रान्तिकारियों की राजनीति का जो श्रम और पूँजी के बीच समझौतापरस्त ताकत के रूप में कार्य करते हुए भ्रम पैदा करती है। इसके असल चरित्र को बेनकाब करना है। एक क्रान्तिकारी पार्टी को यह जांचना पड़ता है कि कौन-कौन इस समझौतापरस्त ताकत में शामिल हैं। ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो ताकत मुख्य खतरा है, वह एक खास राज्य में, एक खास दायरे में चाहे उतना महत्त्व न रखती हो, फिर भी, राष्ट्रीय स्तर पर जो ताकत मुख्य खतरा है, उसका

(शेष पृष्ठ 6 पर)

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-बिल के खिलाफ बिलारी, उ.प्र. में हुई किसान महापंचायत

बिलारी (यूपी) : भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-बिल के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन व अन्य किसान संगठनों के आह्वान पर 25 मार्च को बिलारी, उत्तर प्रदेश में किसान महा पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र आदि कई राज्यों के किसान प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पंचायत में ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) से जुड़े मुरादाबाद व आसपास से आये किसानों ने भी शिरकत की। संगठन की ओर से कॉमरेड सत्यवान ने महापंचायत को सम्बोधित किया। संगठन के पश्चिमी यूपी प्रभारी कॉमरेड शील कुमार भी अन्य किसान प्रतिनिधियों के साथ मंच पर उपस्थित थे। इनमें मेधा पाटकर, हन्नान मोला, चौधरी हरपाल सिंह, पीवी हरगोपाल उल्लेखनीय हैं। महापंचायत का उद्घाटन कॉमरेड रमेश शर्मा द्वारा गाये गाने 'जागो मजदूर-किसान, हर मेहनतकश इन्सान, जल-जंगल-जमीन बचाओ, शुरू हुआ संग्राम' से हुआ।

कॉमरेड सत्यवान का भाषण

अध्यक्ष जी, बहन मेधा जी, राजगोपाल जी, हरपाल सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित विभिन्न संगठनों के नेतागण, आस-पास के गाँवों से आए किसान भाइयों, सबसे पहले मैं भाई हरपाल सिंह व अन्य आयोजक भाइयों को अपने संगठन, ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन और हरियाणा के किसान-खेतमजदूरों की ओर से क्रान्तिकारी बधाई देता हूँ। आप सब किसानों की रोजी-रोटी के एकमात्र आधार कृषि भूमि व किसान-खेतमजदूरों के जीने के अधिकार को बचाने के लिए किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। दोस्तो, गत 24 फरवरी को दिल्ली में संसद के सामने से जो संग्राम शुरू हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की किसान पंचायत उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में मील का एक पत्थर साबित होगी। दो रोज पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों से अपने मन की बात कहने के बहाने रेडियो पर जो कुछ बातें कहीं वे सब ठग विद्या के अलावा कुछ नहीं है। मैं पुरजोर उनका खण्डन करता हूँ। उन्होंने कहा कि 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून आनन फानन में, जल्दबाजी में लाया गया था। यह एक कोरा झूठ है। आप जानते हैं कि कृषि भूमि बचाने के लिए देश के कोने-कोने में किसान लड़े हैं। दादरी, भट्टा पारसोल, अलीगढ़ और टप्पल में यूपी के किसान-खेतमजदूरों ने कंधे से कंधा मिला कर लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हरियाणा में अम्बानी के एसईजेड के लिए 25000 एकड़ जमीन छीनने के खिलाफ हम लड़े हैं। अनेक जगह बहन मेधाजी के झण्डे के नीचे संघर्ष हुए हैं। बंगाल में सिंगुर और नन्दीग्राम में सफल लड़ाइयाँ हुई हैं। उड़ीसा, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र में भूमि बचाने के लिए अंग्रेजों के जमाने के कानून को बदलवाने के लिए लम्बे अर्से तक जो लड़ाइयाँ लड़ी थी उनके दबाव में ही 2013 में भूमि अधिग्रहण का नया कानून बना था। दूसरी बात यह कि उसे लेकर संसद की एक स्थाई कमेटी बनी थी। उस कमेटी में भारतीय जनता पार्टी की संसद में जो मौजूदा स्पीकर हैं, श्रीमती सुमित्रा महाजन, वे खुद उसकी अध्यक्ष थी। ऐसे में, प्रधानमंत्री जी कैसे कह सकते हैं कि यह कानून आनन-फानन में बना था। उन्होंने खुद अपनी बात में कहा कि जब वे सत्ता में नहीं थे तब भाजपा ने इसको समर्थन दिया था लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके जेहन में कुछ बातें आई। यही तो दुर्भाग्य है। जब आप सत्ता के बाहर थे तो आप किसानों की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे। सत्ता में आने के बाद आप उन्हें भूल जाते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने लोगों से पूछा कि मैं राज्यों की अर्थात् मुख्यमंत्रियों की मानूँ या नहीं मानूँ। हमारा कहना है कि विभिन्न पार्टियों के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों में पूँजीपतियों, देशी-विदेशी कम्पनियों के स्वार्थ में सरकार चला रहे हैं। ऐसे में आप जनता से धोखाधड़ी करने वाले उन मुख्यमंत्रियों की बात मानोगे या फिर विशाल जनसमुदाय, शोषित-पीड़ित-उपेक्षित किसानों, देश के कोने-कोने में मेहनतकश लोगों की बात मानोगे? प्रधानमंत्री जी, इस तरह से आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। उन्होंने रेडियो पर कहा था कि 2013 में कांग्रेस ने जो नया काननू बनाया था, उसमें 13 कानून ऐसे छोड़ दिए थे जिनके तहत किसानों की जमीन अंग्रेज के बनाए कानून के तहत ही सस्ते में ली जा सकती थी। इसलिए उन 13 कानूनों को भी किसानों के हित में बदलने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 लाना पड़ा। भाइयो, प्रधानमंत्री जी की यह बात बेहद चालाकीपूर्ण है। इन 13 कानूनों को एक साल के अन्दर बदलने का प्रावधान था। मोदी सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करके एक साल की इस मियाद को आगे बढ़ा सकती थी और मामले को संसद के अन्दर लाकर जनहित में जरूरी बदलाव ला सकती थी। लेकिन आपने ऐसा करने की बजाय, 2013 के पूरे कानून को ही कूड़ेदान में फेंक दिया और काला अध्यादेश जारी कर दिया। आपने बिमारी का इलाज करने की बजाए मरीज को ही मार डाला। आपने तो संसद की देहरी पर माथा टेका था मानो यह (जनतंत्र का) एक मन्दिर हो। लेकिन आपने अपने आचरण में तो संसद के प्रति ऐसी कोई श्रद्धा नहीं दिखाई। आप तो निरंकुश राजा की तरह फरमान जारी कर रहे हैं। आपने अपनी खुद की पार्टी के सांसदों से भी नहीं पूछा। इस मसले को संसद के भीतर लाना उचित नहीं समझा। जाहिर है आप एक फासिस्ट हैं। नाजी हिटलर की तरह आपका आचरण संसदीय जनतंत्र के हत्यारे जैसा है।

किसान महापंचायत में वक्तव्य रखते हुए मेधा पाटकर, मंच पर बैठे हुए कॉ. सत्यवान व शील कुमार

दोस्तो, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार सामाजिक प्रभाव का आंकलन कैसे संभव है? इसमें तो बहुत लम्बा समय लग जाता-किसानों को अफसरों के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाना पड़ता कि मेरी जमीन ले लो। मैं पूछता हूँ मोदीजी, आप सारे हिन्दुस्तान से एक भी किसान ऐसा दिखा दें जिसने अफसर, मंत्री या एम.एल.ए. के पास जाकर भीख मांगी हो कि मेरी जमीन ले लो। हर प्रदेश में हर सरकार ने लाठी-गोली चला कर जबरदस्ती काले कानूनों की ताकत से किसानों की जमीन छीनी है। आपकी ये झूठी बातें नहीं चलेंगी। उन्होंने सवाल उठाया कि भूमि लेने के लिए किसानों की सहमति कैसे लें? एक गाँव सड़क बनाने देगा, 5 किलोमीटर के बाद दूसरा गाँव सड़क नहीं बनाने देगा। इससे तो विकास ही ठप्प हो जाएगा। मोदीजी एक भी ऐसा गाँव दिखा दें जहाँ किसानों ने सड़क बनने से इन्कार किया हो, नहर बनने से रोका हो? मोदीजी सरेआम देश को बरगला रहे हैं। पुन: वे कहते हैं कि जो इण्डस्ट्रियल कोरीडोर (औद्योगिक गलियारा) बनेगा वह सरकार के मालिकाने में होगा, इसलिए लोगों को चिन्ता नहीं करनी चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि बी.ओ.टी. (बिल्ड, ओपरेट एण्ड ट्रांसफर) के तहत आपने प्राइवेट कम्पनियों से बहुत सारे रोड बनवाए हैं, इन सभी का मालिकाना तो सरकार के पास ही है लेकिन इन पर जगह-जगह जो टोल टैक्स लिया जाता है, वह कौन लेता है? प्राइवेट कम्पनियाँ बिना टोल-टैक्स लिए किसी को जाने देती हैं क्या? इसी तरह जनता के धन से बनाए हुए स्कूलों को, स्कूल भवनों को आप शिक्षा भारती (एयरटेल) जैसी प्राइवेट कम्पनियों को सौंप देते हैं। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। आप आबादी के 60-70 प्रतिशत हिस्से के किसान-खेतमजदूरों की रोजी-रोटी के एकमात्र साधन कृषि भूमि को छीन कर पूँजीपतियों को देंगे, विदेशी कम्पनियों को देंगे, यह नहीं चलेगा। हम इसे नामंजूर करते हैं।

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह भूमि अधिग्रहण अध्यादेश-बिल हम किसानों को ताकतवर बनाने के लिए लाए हैं। कैसे? क्या जमीन छीन कर वे किसानों को ताकतवर बनाएंगे? यदि आप किसानों को अच्छा खाद-बीज दें, सस्ता दें, उन्हें डीजल सस्ता दें, समय पर पर्याप्त बिजली दें, नहरी पानी दें, उनकी फसलों को सही दाम पर खरीदें, गन्ने का तुरन्त भुगतान करें तभी तो किसानों की हालत बेहतर होगी। लेकिन यह सब न करके उल्टे उनकी जमीन ही छीन रहे हैं। ऐसा तो कोई दुश्मन ही कर सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मण्डी का इन्तजाम अच्छा होगा। आपको याद होगा कि 2003 में जब केन्द्र में वाजपेयीजी की सरकार थी और राजनाथजी उसमें कृषि मंत्री थे, तब इन्होंने कहा था कि बस, बहुत हुआ, अब हम फसलों का समर्थन मूल्य घोषित तो करेंगे परन्तु समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज आदि खरीदेंगे नहीं। यदि बाजार में आढ़ती-व्यापारी समर्थन मूल्य से कम रेट पर खरीदे तो बकाया रकम किसान हम से ले जाएं। भाइयो, मोदी सरकार यह दस्तूर अब लागू करना चाहती है। मण्डी में जो थोड़ा-बहुत सरकारी नियन्त्रण है, उसको भी खत्म करके फिर से बिचौलियों-प्राइवेट पूँजी के हाथ में मण्डी को देना चाह रही है।

आखिर में, मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में कहीं भी इण्डस्ट्री नहीं पनप रही। एक इण्डस्ट्री लगती है, पाँच बन्द हो जाती हैं। कुछ साल पहले अमेरिका के बड़े-बड़े सारे बैंकों का दिवाला पिट गया था, उनकी इन्श्योरेन्स कम्पनियाँ फेल हो गई थी। सिर्फ हिन्दुस्तान के ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया के पूँजीपतियों के औंधे घड़े पड़े हुए हैं। यह संकट खुद उन्होंने ही पैदा किया है, जनता को चूस-चूस कर इतना कंगाल-खस्ताहाल कर दिया कि इनका बनाया माल बिक नहीं रहा। बहुत ही थोड़े लोगों की खरीदने की ताकत है। इसलिए आज इण्डस्ट्री कहीं नहीं खुल रही हैं। अब इन पूँजीपतियों की ललचायी गिद्धदृष्टि किसानों की बेशकीमती उपजाऊ बहुफसली जमीनों पर है। देश की राजधानी व राज्यों की राजधानियों, राष्ट्रीय राजमार्गों, रेल लाइनों के पास कृषि भूमि को सस्ते में खरीद कर और महंगे रेट पर बेच कर फ्लैट बना माला-माल होना चाहते हैं। ऊपर से तुक्का यह कि गरीबों के लिए सस्ते घर बनाना चाहते हैं। इनकी यह चाल आपको समझनी होगी। ये पूँजीपतियों के विकास और किसानों-मेहनतकशों के विनाश का रास्ता ले रहे हैं। कृषि भमि का कोई मुआवजा हो सकता है क्या? मुआवजे के नाम पर आपके हाथ पर चान्दी के चन्द सिक्के रख देंगे-इससे परिवार चलेगा क्या? किसानों, खेतमजदूरों व पशुपालकों की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियाँ जमीन पर निर्भरशील हैं। असल में यह उनके जीने के अधिकार पर एक भीषण हमला है। मोदी जी जो कानून ला रहे हैं उसका चन्द शब्दों में साफ-साफ मायने यह है कि पूँजीपितयों के स्वार्थ में मनचाही जमीन को, आपकी जमीन, मेरी जमीन, इसकी जमीन, उसकी जमीन को जबरन और आसानी से, सस्ते में हड़पना चाहते हैं। यह हमें मंजूर नहीं है। देश के किसान इसके खिलाफ लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के किसान जब लड़ेंगे तो हरियाणा के किसान कन्धे से कन्धा मिलाकर आपके साथ आएंगे। पंजाब व दूसरे प्रान्तों के भी प्रतिनिधि बैठे हैं। देश के कोने-कोने से यह लड़ाई आगे बढ़ेगी। मैं बिलारी के किसान भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। हम सब मिलकर लड़ेंगे और जैसा कि बहन मेधा ने नारा बुलंद किया है-हम जीतेंगे।

जौनपुर में लगा महिलाओं का शिक्षण-शिविर

जौनपुर (यूपी) : 14-15 फरवरी को खजुरन, बदलापुर, जौनपुर, उ.प्र. में महिलाओं के राज्य स्तरीय शिक्षण शिविर का आयोजन ऑल इण्डिया एम.एस.एस. के बैनर तले किया गया। शिविर का संचालन ऑल इण्डिया एमएसएस की राष्ट्रीय अध्यक्षा व एसयूसीआई(सी) की केन्द्रीय कमेटी सदस्या कॉमरेड छाया मुखर्जी ने किया। शिविर की अध्यक्षता संगठन की राज्य संयोजिका कॉ. रश्मि मालवीय ने की। शिक्षण शिविर में सौ से ज्यादा महिलाओं ने जोश के साथ हिस्सा लिया।

कॉमरेड छाया मुखर्जी ने दिखाया कि समाज एक समय मातृप्रधान था जो विकास क्रम में पुरुष प्रधान समाज में तब्दील हो गया। उन्होंने कहा कि इस समाज में महिलाएं एक तरफ तो पूंजीवादी व्यवस्था की देन महंगाई, बेरोजगारी, कुशिक्षा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, अपसंस्कृति की मार झेल रहीं हैं, दूसरी ओर पुरुष प्रधान समाज होने के नाते महिलाओं को उपभोग की वस्तु के रूप में देखा जाता है। उनके सम्मान व मान-मर्यादा को ठेस पहुंचाई जा रही है। महिलाओं को इस दोहरे शोषण से मुक्ति पाने के लिए संगठित होना पड़ेगा। कॉमरेड शिवदास घोष के विचारों की रोशनी में इसी उद्देश्य को लेकर महिला सांस्कृतिक संगठन की स्थापना की गयी। यह संगठन आज महिलाओं पर होने वाले शोषण, जुल्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहा है।

18 सदस्यीय राज्य कमेटी गठित की गई जिसमें रश्मि मालवीय को अध्यक्ष, वन्दना सिंह को सचिव, कल्याणी राय चौधरी, ज्ञानशीला शर्मा व लता शर्मा को उपाध्यक्ष तथा ऊषा वर्मा को कोषाध्यक्ष एवं शांति मौर्य, बासमति मौर्य प्रभावती मौर्य, किरन चौहान, मीता गुप्ता, सावित्री शर्मा, प्रमिला शर्मा, सीता यादव, रेखा मौर्य, कुसुम मौर्य, तारा यादव व भावना सिंह को कमटी सदस्य चुना गया।

दिल्ली में महिला सम्मेलन का आयोजन

दिल्ली : महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराधों, शराबखोरी व अश्लीलता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 24 मार्च को किशन गंज इलाके में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता आशा रानी ने की। सम्मेलन में बड़ी संख्या में इलाके की महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं पर बढ़ते अपराधों तथा समाज में हो रहे नैतिक-सांस्कृतिक पतन के खिलाफ एक प्रस्ताव सबसे पहले पेश किया गया। सम्मेलन को मुख्य वक्ता एस.यू.सी.आई.(सी)दिल्ली राज्य कमेटी सदस्य के.सी. तिवारी, ऑल इण्डिया एम.एस.एस. की दिल्ली राज्य अध्यक्ष प्रो. सुबोध शर्मा, उपाध्यक्ष एडवोकेट दीपिका जैन, सचिव रितु कौशिक व सचिवमण्डल सदस्य सीता सिंह ने सम्बोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि आज महिलाओं पर भयावह रूप से बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ जोरदार सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन गठित करना समय की मांग है। हर इलाके में महिलाओं को संगठित करते हुए ही हम इस आन्दोलन को मजबूत बना सकते हैं और समाज को सामाजिक-सांस्कृतिक पतन से बचा सकते हैं। सम्मेलन में 13 सदस्यीय समिति का चुनाव किया

गया जिसमें ओमवती को अध्यक्ष, रितु गिरी और बबीता को उपाध्यक्ष व सीमा चौहान को सचिव चुना गया।

ऑल इण्डिया एम.एस.एस. की दिल्ली राज्य कमेटी द्वारा दिल्ली के अन्य इलाकों जैसे सोनिया विहार, बुराड़ी, साकेत, भलस्वा, बृज विहार आदि में भी अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा सभाओं का आयोजन यिका गया, जिनमें इलाके की महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इन सभाओं को दिल्ली राज्य कमेटी सदस्य पुष्पा चमोली, एडवोकेट दीपिका जैन, रितु कौशिक, सीता सिंह तथा आशा रानी ने सम्बोधित किया।

तेलंगाना में शिक्षा बचाओ कमेटी का आन्दोलन

हैदराबाद: स्कूली पाठ्यपुस्तकों में सिर्फ तेलंगाना की ही रचनाओं को शामिल करने के रुझान के ऑल इण्डिया शिक्षा बचाओ कमेटी के तेलंगाना चैप्टर की ओर से 19 मार्च को एससीईआरटी के निदेशक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भाषा व साहित्य के अध्ययन पर जोर देते हुए ऐसे अध्ययन को हर तरह के क्षेत्रवाद और अलगाववाद से मुक्त बनाने की मांग की गई। जाने माने कवि हिमाजवाला, कमेटी के सचिव एस गोविन्दराजुलू व अन्य नामीगिरामी शिक्षाविदों ने आन्दोलन में शिरकत की। इस आन्दोलन के दबाव में निदेशक ने राजय से बाहर की तेलगू रचनाओं को भी पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने का आश्वासन दिया।

एससीईआरटी के निदेशक को ज्ञापन देते हुए शिक्षा बचाओ कमेटी के कार्यकर्ता

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर

''महिला उत्पीड़न : कारण और समाधान'' विषय पर सभा

इलाहाबाद। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ''महिला उत्पीड़न : कारण और समाधान'' विषय पर 13 मार्च को लोहा पार्क, अल्लापुर में, ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) के द्वारा सभा का आयोजन किया गया। सभा में काफी संख्या में महिलाओं ने उत्साह से भागीदारी की।

सभा को कल्याणी रायचौधरी, ज्ञानशीला शर्मा, सुधा त्रिपाठी व एआईएमएसएस की राज्य संयोजिका रश्मि मालवीय ने अपने वक्तव्य रखे। मीडिया में

अश्लील सिनेमा, साहित्य, विज्ञापन, और पोर्नोग्राफी के प्रसारण के साथ ही शराब की दुकानों पर रोक लगाने की मांग की गई। इसके बिना महिलाओं पर होने वाले यौन अत्याचारों को नहीं रोका जा सकता।

कार्यक्रम के प्रारंभ में आशू ठाकुर तथा प्रियंका सिंह ने महिलाओं से सम्बन्धित क्रांतिकारी गीत सुनाए। सभा स्थल पर एआईएमएसएस के पूरे देश में तथा इलाहाबाद में होने वाले आन्दोलनों की चित्रप्रदर्शनी भी लगाई गयी। कार्यक्रम में गीता त्रिपाठी, रेनू गुप्ता, संध्या मिश्रा, रामपति, माया तिवारी, सुष्मिता राय, रागिनी पटेल, उर्मिला शर्मा आदि उपस्थित रहे। सभा का संचालन सुमन शुक्ला ने किया।

गैंगरेप के खिलाफ जताया रोष

पटना : डीएवी स्कूल की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के खिलाफ ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन पटना जिला कमिटी के तत्वावधान में 25 मार्च को विरोध मार्च निकाल कर रोष जताया। जुलूस गांधी मैदान स्थित शहीद भगत सिंह चौक से प्रारंभ हुआ, जो जेपी गोलम्बर, फ्रेजर रोड होते हुए डाक बंगला चौराहा तक गया। वहां पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि 'डीएवी स्कूल के पूर्व प्राचार्य रामानुजन को तुरंत गिरफ्तार करो', 'बलात्कारियों को अविलम्ब गिरफ्तार कर दृष्टांतमूलक सजा दो' 'डीएवी स्कूल में चल रहे शिक्षा माफिया का पर्दाफाश करो', 'शराबखोरी-नशाखोरी पर रोक लगाओ', 'लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी करो', 'अश्लील सिनेमा-साहित्य पर रोक लगाओ'

सभा को संगठन की राज्य सचिव साधना मिश्रा, अरविन्द महिला कॉलेज की पूर्व प्राध्यापिका चित्रा वैश्य, प्रो. भारती एस कुमार, एडवोकेट इन्दिरा लक्ष्मी तथा संगठन की नेत्री अनामिका, मालविका राय, नम्रता, पुष्पा, सीमा देवी आदि ने भी सम्बोधित किया। वक्ताओं ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते जुल्म पर रोक लगाने के लिए समाज में उच्च नीति-नैतिकता के आधार पर महिला आंदोलन निर्मित करने पर बल दिया।

गैंगरेप के खिलाफ पटना की सड़कों पर उतरी महिलाएं

देश ने क्रान्तिकारियों को किया याद, उनके अधूरे सपने को पूरा करने की ली शपथ

हर साल शहीद भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, राजगुरु व सुखदेव सरीखे क्रान्तिकारियों के शहीदी दिवस जैसे ही आते हैं, पूंजीवादी शोषण की चक्की में पिसे हुए करोड़ों लोगों के पीले जर्द चेहरे हमें याद दिलाते हैं कि हर तरह के शोषण का खात्मा करने का उन क्रान्तिकारियों का सपना आज तक भी साकार नहीं हो पाया है, अधूरा है। आज जब महिलाएं उत्पीड़ित और प्रताड़ित हैं, नये सिरे से द्वेष के बीज बोये जा रहे हैं, साम्प्रदायिक दंगे-फसाद में अनगिनत लोग मारे जा रहे हैं –ये सब आये दिन के मामले होते जा रहे हैं, इन बहादुर शहीदों की जीवनियां छात्र-नौजवानों के लिए राह रोशन करने वाली रोशनी का काम कर सकती हैं।

इन शहीदों के सपनों को साकार करते हुए शोषणमुक्त समाज कायम करने की शपथ लिये हुए संगठनों, ऑल इण्डिया डीएसओ व ऑल इण्डिया डीवाईओ ने इन क्रान्तिकारियों का शहीदत दिवस यथोचित सम्मान के साथ देश भर में मनाया। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये। कार्यक्रम की शुरूआत में उपस्थित जनसमूह नें शहीदों की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की।

पंजाब की यूनिट ने पंजाबी में शहीद भगत सिंह दा जीवन संघर्ष शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की।

झारखण्ड में ऑल इण्डिया डीवाईओं द्वारा सरायकेला-खरसवां जिला के आदित्यपुर, चाझिडल के आधारडीह गांव, चैनपुर में 23 मार्च को शहीद-ए- आज़म भगत सिंह का 84वां शहीदी दिवस मनाया गया। इस दिन घाटशिला कॉलेज में शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहीदी दिवस पर एक सभा की गई। सभा को प्रो. नरेश, डा. कविता चौधरी, प्रो. मित्रेश्वर, स्कूल शिक्षकों ने सम्बोधित किया। इसके बाद निकाले गये मशाल जुलूस में 400 के आसपास बच्चों, छात्रों, नौजवानों ने हिस्सा लिया। शहीद भगत सिंह पर बनी फिल्म दिखाई गई।

हैदराबाद में ऑल इण्डिया डीएसओ व ऑल इण्डिया डीवाईओं ने मसाब टैंक पोलीटैक्निक कॉलेज, बालनगर आईटीआई और मुर्शिदाबाद आईटीआई आदि कई कॉलेजों में 23 से 30 मार्च तक एक सप्ताह व्यापी शहीद भगत सिंह यादगार कार्यक्रम किये गये। खैराताबाद मेन चौराहे पर कैण्डल मार्च किया गया।

गुजरात में सूरत में ऑल इण्डिया डीएसओ की पहल पर महान शहीदों को यथोचित सम्मान के साथ याद किया गया। इस अवसर पर एक नाटक भी मंचित किया गया।

कानपुर: शहीद ए आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर जन-प्रतिरोध आन्दोलन समिति कानपुर एवं ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. की कानपुर इकाई द्वारा संयुक्त रूप से कल्याणपुर में बगिया क्रासिंग पर सभा की गई। एक पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई। वक्ताओं ने भगत सिंह के जीवन संघर्षों पर विस्तार में चर्चा की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जन-प्रतिरोध आन्दोलन समिति के जिला अध्यक्ष बृजेश सिंह, जिला सचिव अरविन्द अवस्थी, ऑल इण्डिया डीएसओ के जिला अध्यक्ष दिनेश महन्त, समाजसेवी वालेन्द्र कटियार आदि ने हिस्सा लिया।

मुरादाबाद : शहीदों की यादगार सभा हुई जिसे कॉ. विजयपाल सिंह ने सम्बोधित किया।

जौनपुर, उ.प्र. भारतीय आजादी आन्दोलन के गैर समझौतावादी धारा के महान क्रान्तिकारी शहीद ए आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहादत दिवस पर 23 मार्च को ऑल इण्डिया डी.एस.ओ., ऑल इण्डिया डी. वाई.ओ. व कॉमसोमोल संगठन की ओर से जौनपुर जिले में श्री कृष्णा नगर रेलवे स्टेशन, इन्दिरा चौक, बटाऊबीर चौराहा, घनश्यामपुर बाजार, महाराजगंज बाजार, हरपालगंज रेलवे स्टेशन, सिंगरामऊ तिराहा, कुशहाँ बाजार, बरैयाँ, रजनीपुर, सरदारनगर, पहितियापुर गाँव, बहरा व अन्य कई जगहों पर कैण्डिल मार्च, माल्यार्पण, बैजवियरिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। जौनपुर शहर स्थित भगतसिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. ने 23 मार्च से 29 मार्च तक 'साप्ताहिक कार्यक्रम' चलाया। जिसमें मल्लूपुर, रामपुर, रतासी, साढ़ापुर, पडरी व अन्य जगहों पर बैज धारण व श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम हुआ। 28 मार्च को बबुरा गाँव में एक कैण्डिल मार्च व जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों बच्चों, छात्र-युवाओं के अलावा क्षेत्र के अन्य लोग भी शामिल हुए।

अमरोहा: 23 मार्च के दिन संगठन की जिला ईकाई द्वारा देश के महान क्रान्तिकारी भगत सिंह, राजगुरू, सुखदेव का शहादत दिवस जिला अमरोहा भवालपुर व थारापुर के कमलेश गिल हाई स्कूल व याद गूजर रोड स्थित अमन पब्लिक स्कूल में मनाया गया। गजरौला में क्रान्तिकारियों को श्रद्धांजलि स्वरूप एक जुलूस रेलवे स्टेशन से शुरू कर बस्ती होते हुए इन्द्रा चौक पर सभा कर समाप्त किया गया। सभा में जिला संयोजक नासिर अली के अतिरिक्त संगठन के जिला सचिव नौ बहार सिंह व मूलचंद गिल आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

वाराणसी (यूपी) : एआईडीवाईओ के बैनर तले 23 मार्च को महान क्रान्तिकारी शहीद-ए-आजम भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरू के शहादत दिवस के अवसर पर छात्र-नौजवानों ने शहर में शहीद उद्यान पार्क सिगरा एवं

(शेष पृष्ठ 8 पर)

म.प्र. में राज्य स्तरीय 'सेमेस्टर हटाओ यात्रा' को मिल रहा है भारी जनसमर्थन

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, शिक्षा में सुधार के नाम पर लागू की सेमेस्टर प्रणाली के दुष्परिणाम शुरूआत से ही समझ में आने लगे थे। सेमेस्टर प्रणाली में फीस वृद्वि तो की ही साथ ही इसने अनिश्चितताओं को जन्म दिया। शुरूआत से ही सेमेस्टर प्रणाली का शैक्षणिक कलैण्डर पटरी पर नहीं था। छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों ने इसकी खिलाफत की। छात्र संगठन ऑल इंडिया डी.एस.ओ. सेमेस्टर प्रणाली की शुरूआत से ही छात्र आंदोलन संचालित करता आ रहा है। आंदोलन के दबाव ने ही सरकार को बार-बार सेमेस्टर प्रणाली को वापिस लेने के बयान देने के लिए मजबूर किया। सरकार ने 29 सितम्बर को सेमेस्टर प्रणाली पर वोटिंग कराने का निर्णय लिया लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी कर वोटिंग नही कराई। यदि सरकार वोटिंग कराती तो समस्त छात्र समुदाय इसके खिलाफ ही वोटिंग करता। जब सेमेस्टर प्रणाली के मुद्दे पर प्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलपतियों की मीटिंग हुई तो इसमें अधिकांश कुलपतियों ने सेमेस्टर प्रणाली को वापिस लेने की बात कही। छात्रों व आम जनता के बीच यह भ्रम पैदा हो गया कि सरकार सेमेस्टर प्रणाली को वापिस ले रही है तब छात्र संगठन ऑल इंडिया डी.एस.ओ. ने आंदोलन को और तेज करते हुए एक राज्य स्तरीय सेमेस्टर हटाओ यात्रा करने का निर्णय लिया। सेमेस्टर प्रणाली हटाने की मांग पर छात्र संगठन ऑल इंडिया डी.एस.ओ. के द्वारा 16 मार्च से 10 अप्रैल तक म.प्र. के विभिन्न जिलों में राज्य स्तरीय सेमेस्टर हटाओ यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का प्रथम चरण 16 मार्च से 20 मार्च तक रहा व सेमेस्टर हटाओ यात्रा का द्वितीय चरण 23 मार्च से 27 मार्च तक रहा इस दौरान यात्रा 15 जिलों में गई वहाँ छात्रों, शिक्षकों शिक्षाप्रेमी जनता द्वारा यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ व जबरदस्त समर्थन मिला। प्रथम चरण में उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय पर भी यात्रा पहुँची। यात्रा के प्रथम चरण का समापन 20 मार्च को इंदौर के देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय पर हुआ। सेमेस्टर हटाओ यात्रा के द्वितीय चरण का समापन 27 मार्च को ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय पर हुआ। सेमेस्टर हटाओ यात्रा में डी.एस.ओ. कार्यकर्ताओं द्वारा धन संग्रह किया गया। सेमेस्टर प्रणाली की दुर्दशा पर एक विशेषांक 'आगाज' भी छापा गया। सेमेस्टर प्रणाली पर रचित नुक्कड़ नाटक व गीत आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। कॉलेज परिसरों के अलावा क्रांतिकारियों, मनीषियों के चौराहों पर पुष्पार्पण कार्यक्रम व सभाएं की गई। यात्रा में शामिल साथियों के खाने की व ठहरने की व्यवस्था समाजसेवी संस्थाओं व स्थानीय जन सहयोग से की गई। यात्रा को डी.एस.ओ. के अखिल भारतीय सचिव मंडल सदस्य कॉ. मुदित भट्नागर, कॉ. सचिन जैन, अखिल भारतीय काउन्सिल सदस्य कॉ. विनोद लोगरिया, कॉ. अजीतसिंह पवार, कॉ. श्रुति शिवहरे, कॉ. कंचना, कॉ. नित्या ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने सेमेस्टर प्रणाली के दुष्परिणाम व शिक्षा क्षेत्र में पूंजी निवेश की खिलाफत की व संगठित छात्र आंदोलन को ही एकमात्र विकल्प बताया। सेमेस्टर हटाओ यात्रा का अगला चरण 30-31 मार्च को जबलपुर में रहेगा। अंतिम चरण 6 अप्रैल को सागर से प्रारम्भ होगा व सेमेस्टर हटाओ यात्रा का समापन 10 अप्रैल को प्रदेश की राजधानी भोपाल में विशाल छात्र प्रदर्शन के साथ होगा।

क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं का काम...

(पृष्ठ 2 का शेष)

मुकाबला उस खास राज्य में भी करना होगा, क्योंकि, नहीं तो कल उस राज्य में भी वह मुख्य खतरे के रूप में उभर सकती है। वह अपनी जड़ जमाए इससे पहले ही हमें उसे उखाड़ फेंकना है। कोई दूसरी ताकत ऐसी भी हो सकती है जो अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य खतरा नहीं है, लेकिन नकली क्रान्तिकारी छवि पैदा करके पश्चिम बंगाल में मुख्य खतरा हो गई है–मैं इस विशेष मामले में सबसे पहले इसका ही मुकाबला करूँगा, यद्यपि जो ताकत पहले से ही राष्ट्रीय तौर पर मुख्य खतरा है, उसका मुकाबला करने के महत्त्व को भी मुझे कम नहीं कर देना चाहिए। क्योंकि जो ताकत इस राज्य में अब मुख्य खतरा है, यदि वह कमजोर पड़ती है तो जो ताकत राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य खतरा है, कल यहाँ उसका स्थान ले लेगी जब तक कि इस दौरान इसका मुकाबला करके इसे परास्त न कर दिया जाए। यदि वह ताकत राजनीतिक तौर से लैस है और उसका मुकाबला करने के काम में हम नाकामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पैदा होने वाली रिक्तता को वह भर देगी।

इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं की चेतना के स्तर को ऊपर उठाना और सभी क्षेत्रों में उनकी राजनीतिक पहलकदमी को बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है। गत कुछ अर्से से मैं राजनीतिक पहलकदमी बढ़ाने के सवाल को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और प्रत्येक कार्यकर्ता की व्यक्तिगत व राजनीतिक पहलकदमी को बढ़ाने का आग्रह बार-बार करता रहा हूँ। मैंने यह भी जोर दिया है कि चाहे इसमें जोखिम हो, चाहे कुछ गलतियाँ हो जाएं, फिर भी अपने दम पर जन आन्दोलन संगठित करने और उसको नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास करो। केवल पार्टी सिद्धान्त, पार्टी की पूँजीवाद-विरोधी क्रान्ति की मूल राजनीतिक लाइन आदि को जहाँ तक आप समझे हैं उसके अनुरूप आन्दोलन संचालित करने की बात को मत भूलिएगा। यदि आप कुछ गलतियाँ भी कर देते हैं तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। गलती होने पर नेताओं को भी कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए और पहलकदमी पर ठण्डा पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसे मामले में नेताओं को जो करना चाहिए वह है : गलती को सहानुभूतिपूर्वक बताना और उसको दुरुस्त करना। लेकिन कड़ी आलोचना द्वारा पहलकदमी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ''क्यों उसने बिना सलाह-मशवरे के यह किया''–इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिएं। कॉमरेडों की पहलकदमी को प्रोत्साहित करिए, उन्हें अपनी बुद्धि से काम करने दीजिए, उन्हें काम करने दो; निश्चित ही, अराजक तरीके से नहीं। एक तरफ उन्हें पार्टी की मुख्य राजनीतिक लाइन की अपनी समझ को बढ़ाने दो और इसमें पारंगत होने दो। दूसरी तरफ अपनी समझ के अनुसार जिस तरीके से भी चाहते हैं, उनको पार्टी लाइन के मुताबिक जनआन्दोलन गठित करने का मौका देना चाहिए। यदि वे गलतियाँ करें तो उनको सुधारना है, लेकिन कभी मत कहो: ''क्यों मेरे से बिना चर्चा किए आपने यह किया है?'' यह है जिसे मैं पदाधिकारियों के सामने जोर देकर रखना चाहता हूँ। क्योंकि सबसे ज्यादा कमी उचित प्रकार से तैयार राजनीतिक कैडरों की है। इस मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हमें समाज की इस वर्तमान अवस्था में राजनीतिक उथल-पुथल से उठने वाली भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करना है–सवाल जो नकली क्रान्तिकारियों के बीच उठते हैं, भ्रान्तियाँ जो प्रगतिशील कहे जाने वालों के बीच पैदा होती हैं, भ्रान्तियाँ जो दूसरी पार्टियों की पार्टी-पाँति में व्याप्त हैं। यह सोच ठीक नहीं है कि जो भी प्रभावित हैं वे सचेत रूप से या पैसे के लिए एजेण्ट का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से सोचना मामले का अतिसरलीकरण करना होगा। उनमें से अनेक इसलिए इन ताकतों के पीछे लगे हैं, क्योंकि उन्हें राजनीति की सही समझ नहीं है। हमें उस भ्रम को दूर करना है जिससे वे ग्रस्त हैं, हमें जन साधारण में व्याप्त भ्रम को दूर करना है। भ्रम दूर करने और सही राजनीति की व्याख्या करने का यह कष्टसाध्य कार्य केवल ट्रेण्ड और समर्पित कैडरों द्वारा ही पूरा किया जा सकता है जिनमें पहलकदमी है, नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता है और जो पार्टी की राजनीति की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं तथा बिना गड्डमड्ड किए मूल राजनीतिक लाइन पर कायम रह सकते हैं। हमें ऐसे कैडरों की जरूरत है। हमारे अनेक बेहतरीन कॉमरेडों के मामले में मैं देखता हूँ कि चर्चाओं के दौरान विरोधियों द्वारा उन्हें उत्तेजित किया जा सकता है और एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु पर धकेला जा सकता है। उन्हें चर्चा में उलझाया जा सकता है और मूल बिन्दु से दूर ले जाया जा सकता है। चर्चा-बहसों के दौरान सजग न रहने के चलते, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने की झोंक में वे आसानी से उस बात से भटक जा सकते हैं जो वे कहना चाहते थे। यह इसलिए होता है कि वे राजनीतिक तौर से पूरे परिपक्व नहीं हैं। वे चर्चा के उद्देश्य के प्रति सचेत नहीं हैं। वे जो परिपक्व और पारंगत हैं उन्हें मूल बिन्दु से हटाया नहीं जा सकता है चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले। बल्कि दूसरे जब चर्चा को दिशाहीन बनाने का प्रयास भी करें तो वे ऐसा होने से रोकते हैं और चर्चा को पुन: सही रास्ते पर ले आते हैं। यदि दूसरे मूल मुद्दे से खिसकना भी चाहें तो वे जानते हैं कि उन्हें मजबूती से कैसे पकड़ कर रखा जाए जैसे एक बढ़िया मछुआरा मछली को पकड़े रहता है। क्या पारंगत मछुआरे की पकड़ से मछली निकल सकती है? यदि ये लोग आपको चकमा देते हैं, तो इसके मायने हैं आप पारंगत नहीं हैं; नौसीखिए हैं। यदि कोई परिपक्व यानी तजुर्बेकार है तो कोई भी उसकी पकड़ से प्रयास करने पर भी निकल नहीं सकता है। यह कहना आसान है लेकिन इसकी गहरी समझ इतनी आसान नहीं है। इसके लिए कैडरों को तैयार करना पड़ता है। क्या यह समझ औपचारिक, पण्डिताऊ क्लासों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। मार्क्सवाद की थ्योरियों पर शैक्षणिक क्लासों, जनरल क्लासों की जरूरत है। जब तक इनका अध्ययन नहीं किया जाता और पकड़ हासिल नहीं की जाती तथा व्यवहार के तजुर्बों को सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ जोड़ा नहीं जाता, कोई भी अपनी समझदारी को तेज नहीं कर सकता है। यहाँ भी बहुत से पुराने, तजुर्बेकार कॉमरेड हैं जिन्होंने बहुत सी बातें तजुर्बे से सीखीं हैं, लेकिन क्लासीकल मार्क्सवाद के अध्ययन को और इसकी चर्चाओं व अभिव्यक्तियों से परिचित होने को जरूरी नहीं समझते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने मूल लाइन को तो समझ ही लिया है, फिर और अध्ययन की क्या जरूरत है? नहीं, यह नजरिया ठीक नहीं है।

ऐसा अध्ययन, ऐसा ज्ञान नितांत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी सोच, कार्यकलाप और काम करने की क्षमता को तेज बनाने व बहुमुखी आयाम प्रदान करने, अपने को व्यापक रूप से लैस करने, खुद को सभी स्तरों पर काम करने के योग्य बनाने, सभी दिशाओं में अपने को विकसित करने के लिए यह बहुत जरूरी है। जो भी अवसर हमें मिलते हैं, उनका भरपूर उपयोग हमें करना चाहिए। एक तरफ हमें अध्ययन करना चाहिए, चर्चाएं चलानी चाहिएं और समझदारी की बेहतर स्पष्टता हासिल करने के लिए विचारों का दोस्ताना आदान-प्रदान व बहस-मुबाहिसा करना चाहिए। दूसरी तरफ हमें जन आन्दोलनों को नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। यदि हम इसे दक्षता से न कर सके तब भी, तथा आन्दोलनों से उपजी समस्याओं के समाधान के लिए रचनात्मक सुझाव पेश करने चाहिएं। इस प्रकार से हम अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे। सतत सामूहिक सहचर्य, सतत सामूहिक चर्चा और सतत सामूहिक कार्यकलाप–ऐसा होना चाहिए हमारा जीने का ढंग। कृपया याद रखिए कि कोई भी चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से यह शुरू हो सकती है, अन्तत: इसे राजनीतिक बना देना चाहिए। प्रयोग-व्यवहार के बिना कुछ भी नहीं सीखा जा सकता है। अत: कैडरों को इसी तरह तैयार करना है और यह सीखने का अवसर उन्हें दिया जाना चाहिए। इसलिए, व्यक्तिगत पहलकदमी विकसित करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। जहाँ इसके लिए व्यक्तिगत प्रयास जरूरी हैं, वहीं कमेटी कार्यप्रणाली और नेतृत्व के काम करने के ढंग में सुधार लाने के माध्यम से भी इसे हासिल करने का प्रयास होना चाहिए। कमेटी की कार्यप्रणाली में सुधार से मेरा अभिप्राय है कि मीटिंगों में कैडरों को चर्चा का अधिकाधिक अवसर दिया जाना चाहिए। जो वे कहते हैं, वह हो सकता है कि कष्टप्रद, व्यर्थ या पुनरावृत्ति हो, लेकिन फिर भी यह देखने के लिए कि वे बहस के माध्यम से एक लाइन का निर्धारण कर सकते हैं, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। अत्यन्त धैर्य की आवश्यकता है, हमें सही तरीके से बॉडियों का सामूहिक संचालन हासिल करने के लिए अत्यन्त धैर्य के साथ प्रयास करना चाहिए। यदि हम महसूस करें कि वे फिजूल बातों में उलझ रहे हैं, दूसरों को उत्तेजित कर रहे हैं या फिजूल समय बर्बाद कर रहे हैं तब इसे नियंत्रित करना है, लेकिन नियन्त्रण लागू करने के चलते बहस बन्द नहीं कर देनी चाहिए। जब एक फैसला लेना ही हो, क्योंक पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है और ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है तथा और ज्यादा देरी काम में रुकावट पैदा करेगी–ऐसे मामलों में हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन हमारा तरीका ऐसा होना चाहिए कि चर्चा के जोश पर ठण्डा पानी न पड़ जाए। वे अपने दिमागों को झकझोर रहे हैं। चर्चा-बहस से विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ सूत्रबद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं–नियंत्रण कायम करने के प्रयास में इन सब रुझानों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें उन रुझानों के प्रति चौकस रहना चाहिए जो चर्चा के लिए उनकी झोंक में उजागर होते हैं। सिर्फ बहस के लिए बहस करना, दिखावा करना, निरुद्देश्य बहस को लम्बी करते जाना–ये रुझान हैं, जिनसे उनको मुक्त करना होगा। उनको एहसास होना चाहिए कि चर्चाएं एक सही नतीजे पर पहुँचने के लिए, एक मुद्दे को सूक्ष्मता से समझने के लिए, इसे स्पष्टता से प्रस्तुत करने के लिए हैं। मूल बिन्दु को संक्षेप में पेश करना और इसे यथासंभव स्पष्टता से प्रस्तुत करना एक बात है जबकि चर्चा को उद्देश्यहीन वाद-विवादों द्वारा लम्बी करते जाना, जो भी स्पष्टता पहले से है उसे नष्ट कर देना और इस प्रकार मुद्दे को और भी अस्पष्ट बना देना बिल्कुल दूसरी बात है। हमें इस नुकसानदायक रुझान को दूर करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। लेकिन मार्गदर्शन का मायने चर्चा के लिए, तर्क-वितर्क के लिए उत्साह को समाप्त करना नहीं है। जिस प्रकार इस नुकसानदायक रुझान के बारे में उनको बताना है, उसी प्रकार चर्चा-बहस के लिए उनके उत्साह को भी बरकरार रखना है। यह मुश्किल काम है और नेताओं को सीखना पड़ेगा कि इसे कैसे किया जाए। हम उनकी आलोचना और प्रताड़ना करके एक ऐसी स्थिति पैदा न कर दें जहाँ उनकी बोलने की इच्छा और उत्साह में कमी आ जाए और वे बात करने में भी हिचकें–ऐसा कभी नहीं होने देना चाहिए। बल्कि हमें उन्हें इस प्रकार गाइड करना चाहिए कि भविष्य में चर्चाओं में भाग लेने की उनकी इच्छा और भी बढ़े। इस बारे में सिर्फ उनका ध्यान आकर्षित करना है ताकि वे समझ सकें कि कहाँ और कैसे फिजूल बहस और अत्यधिक बातें करने का रुझान उनकी चर्चा के

(शेष पृष्ठ 7 पर)

भवन निर्माण कारीगर मजदूरों का क्षेत्रीय सम्मेलन

तोशाम (हरियाणा) : 23 मार्च को जिला भिवानी के तोशाम ब्लॉक के भवन निर्माण कारीगर-मजदूरों का सम्मेलन पंचायत भवन में आयोजित हुआ जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों मजदूर प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सबसे पहले आजादी आन्दोलन की समझौताहीन संघर्ष की धारा के क्रान्तिकारी योद्धाओं, शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की तस्वीर पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजली दी गई। सम्मेलन की अध्यक्षता भवन निर्माण कारीगर-मजदूर यूनियन हरियाणा सम्बन्धित एआईयूटीयूसी के तोशाम प्रधान हवासिंह ने की। सम्मेलन के मुख्य वक्ता यूनियन के राज्य प्रधान रामफल के अलावा यूनियन के कोषाध्यक्ष राजकुमार जांगड़ा, जिला सचिव धर्मवीर सिंह, कर्मचारी नेता बस्ती राम, सुखबीर, रोहताश, मंगल सिंह आदि ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया।

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए राज्य प्रधान रामफल ने कहा कि भवन निर्माण मजदूर-कारीगरों ने बहुत सालों के अपने तजुर्बे के आधार पर गृह निर्माण की वैज्ञानिक प्रणाली निर्मित की है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में इनके लगातार श्रमदान से ही युग-युग से गांव-शहरों के भवन, मकान आदि बने हैं और सभ्यता का निर्माण हुआ है। इन सब को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना चाहिए। सरकार की ओर से आर्थिक सहायता, सुविधाएं, हितलाभ और पूरी मान-मर्यादा दी जानी चाहिए। लेकिन सरकारों का रवैया उनके प्रति उदासीन है। अभी तक भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का आधारभूत ढांचा ही नहीं है। हर जिला में पंजीकरण कार्यालय तक नहीं हैं। पर्याप्त स्टाफ नहीं है। रजिस्ट्रेशन व सामाजिक सुरक्षा लाभ पाने की प्रक्रिया जटिल होने, तरह तरह की नाजायज शर्तें थोपी जाने और बेमतलब कागजी कार्रवाई बढ़ जाने से आज तक बहुत ही कम मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो पाया है और ज्यादातर मजदूर-कारीगर इन सुविधाओं का लाभ पाने से वंचित हैं। कारीगर-मजदूरों को साल भर काम नहीं मिलता है। ठेकेदार-मालिक दिहाड़ी मार लेते हैं। इतनी कम दिहाड़ी-मजदूरी मिलती है कि उसमें गुजारा नहीं होता है। देश-प्रदेश में श्रम कानूनों में मजदूर-विरोधी संशोधन करके श्रम अधिकारों पर हमले किये जा रहे हैं। आज सभी सरकारें विकास का राग अलाप रही हैं लेकिन बिना रोजगार के कैसा विकास और किसका विकास? महंगाई-बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। शिक्षा-इलाज पाना लोगों की पहुँच से बाहर होता जा रहा है। जनवादी अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों व कदमों के खिलाफ आन्दोलन तेज करने के लिए उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया। मजदूर इस शोषणमूलक पूँजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंक करके और समाजवाद कायम करके मानव द्वारा मानव के शोषण से मुक्ति पा सकते हैं।

भवन निर्माण कारीगर-मजदूरों के रजिस्ट्रेशन व कल्याण बोर्ड से लाभ पाने की प्रक्रिया सरल बनाने, 90 दिन काम किया यह नियोक्ताओं से लिखवा कर लाने की शर्त और कन्यादान का लाभ पाने के लिए विवाह पंजीकरण की शर्त हटाने, कल्याणकारी स्कीमों के लिए आर्थिक सहायता राशि बढ़ाने, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने, पूरी तरह ठीक होने तक मरीज के इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन किये जाने, पूरे साल काम का इन्तजाम करने व तब तक बेरोजगारी भत्ता देने, गांव-शहर में मुफ्त प्लाट देने और मकान बनाने के लिए 5 लाख का लोन आसान किश्तों पर देने की प्रमुख माँगों पर आन्दोलन गठित करने का निर्णय लिया गया।

सम्मेलन में सर्वसम्मति से 21 सदस्यीय तहसील कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष हवा सिंह, उपाध्यक्ष विनोद, सचिव मंगल सिंह, सहसचिव दलबीर सर्वसम्मति से चुने गये।

जन समस्या संघर्ष मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन

सागर (म.प्र.) : 17 मार्च को जन समस्या संघर्ष मोर्चा द्वारा प्रबंधक, एस्सेल विद्युत वितरण प्रा.लि. कंपनी सागर को बाघराज वार्ड की लाल टोरिया पर अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास के पास लगे विद्युत खम्बे को बदलने हेतु ज्ञापन सौपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि उक्त खम्बा लम्बे समय से टेडा होने व इसकी सूचना कई बार एक्सेल विद्युत वितरण प्रा.लि.कंपनी को दी जाने के बावजूद आज तक कोई भी कार्यवाही नही हुई। वर्तमान में खम्बा गिरने से उसमे लगी तारें जमीन पर गिर गई हैं। कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है जिसमें लोगों को जान जाने का जाखिम पैदा हो गया है। उक्त खम्बे को शीघ्र बदला जाये एवं उक्त खम्बे मे आवश्यकताओं से अधिक कनेक्शन न दिये जायें ताकि उक्त खम्बे का नुकसान न हो जिसमें प्रबंधक महोदय ने शीघ्र अति शीघ्र ठीक करने को आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में मोर्चा के संयोंजक कॉ. तुलसी चढार एवं एड.अशोक कुशवाहा, जयश्री चढार, रामसिंह कुशवाहा आदि शामिल थे।

बच्चियों पर बढ़ते अपराध व शराब नीति के खिलाफ धरना

दुर्ग (छ.ग.) : 20 मार्च को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) जिला संगठन समिति दुर्ग छ.ग. के द्वारा उत्कल नगर दुर्ग की गायब हुई एक गरीब बालिका वनीता गाड़ा को ढूंढने, विजय नगर दुर्ग की 9 वर्षीय बालिका के साथ अनाचार व बर्बर हत्या, एक्सीडेन्ट में गरीब बालिका पिंकी ठाकुर गया नगर दुर्ग में हुई दर्दनाक मौत के जिम्मेदार दोषियों को सजा देने, महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ते अपराध रोकने तथा सरकार की शराब नीति बदलने की मांग पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कचहरी चौक दुर्ग में किया गया और कलेक्टर दुर्ग को मुख्यमंत्री छ.ग. के नाम ज्ञापन सौपा गया। धरने को सम्बोधित करते हुए पार्टी के कॉ. विश्वजीत हारोडे ने कहा कि जब गरीबों पर कोई अपराध हो जिसमें रसूखदार व अमीर शामिल हो तो गरीबों को न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। यह भी देखने को मिलता है कि गरीबों को न्याय दिलाने में प्रशासन उदासीन बना रहता है। वहीं दूसरी ओर आम जनता को शराब में इसलिए डूबोया जा रहा है ताकि उसकी विचार शक्ति नष्ट हो जाए, अपने ऊपर हो रहे जुल्म, अत्याचार व शोषण के कारणों का वे विश्लेषण न कर पायें, संगठित होकर आंदोलन के रास्ते न चले जाएं। उन्होंने आम लोगों से इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए जोरदार जनआंदोलन संगठित करने की अपील की।

बेमौसमी बारिश व ओलाबारी से खराब फसल के मुआवजे की उठाई मांग

भोपाल (मध्य प्रदेश) : पिछले दिनों मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेमौसमी बारिश व ओलाबारी से फसलें चौपट हो गई । किसान बर्बादी के कगार पर आ गये हैं। ये लगातार तीसरा साल है जब किसान मौसम की मार झेल रहे हैं। किसानों को फसल का मुआवजा देने, बीमा कम्पनी द्वारा किसान कार्ड के जरिए बीमा के प्रावधान को मुहैया कराने, किसानों के सभी तरह के कर्जे माफ करने, अगली फसल के लिए सस्ते खाद, बीज व कीटनाशक सुलभ कराने, बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे नकली खाद, बीज व कीटनाशकों की रोकथाम करने और न्यूनतम दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग करते हुए किसान खेतिहर मजदूर संगठन की म.प्र. इकाई की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर संगठन के राज्याध्यक्ष कॉ. उमाप्रसाद, राज्य सचिव कॉ. मनीष श्रीवास्तव व मंजीत पटेल उपस्थित रहे।

क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं का काम..!!

(पृष्ठ 6 का शेष)

तरीके में निहित है। इस प्रकार कैडरों को भरपूर सहायता प्रदान करनी है। इस मामले में सामूहिक कार्यप्रणाली को गुणात्मक रूप से परिवर्तित करना है।

पिछले सत्र में मैंने बड़े दुख के साथ कहा था कि दूसरों द्वारा राय व्यक्त की जा रही है कि हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, जब वे कहते हैं–''आपके कार्यकर्ता बहुत सचेत और बहुत अनुशासित हैं और आपकी पार्टी अच्छी तरह से तैयार क्रान्तिकारी पार्टी है''–कॉमरेडों के अन्दर आत्मतुष्टी पैदा कर रही है। इसके बारे में मैंने पहले भी चेतावनी दी थी और अब भी इसे दोहराना चाहता हूँ। हमें खुद समझना चाहिए कि हमारी कमजोरी कहाँ पर है। बंगाली भाषा में एक कहावत है कि ''झाड़ियों के 'जंगल' में जंगली बिल्ली भी बाघ होती है।'' हमारा इस प्रकार का 'बाघ' होना बेमानी है। हो सकता है दूसरी पार्टियाँ किसी काम की न हों; हो सकता है वे बेईमान हों, अनुशासनहीन हों और वे कुकर्मों में लिप्त रहती हैं जबकि हम ऐसे नहीं हैं। तो क्या हुआ? दूसरे कुछ हासिल नहीं कर सके लेकिन हम कुछ कुर्बानी कर सके; दूसरे कुछ नहीं समझते हैं लेकिन हमने कुछ राजनीति शब्दावली सीख ली है–इससे लाभ क्या है? क्या इनके माध्यम से हम क्रान्तिकारी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं? इसीलिए मैं कह रहा था कि ''झाड़ियों के 'जंगल' में बाघ'' जैसा होने से कोई फायदा नहीं है। ''हमारे कैडर बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं''–बार-बार यह सुनकर मुझे गुस्सा आता है। क्योंकि इसका सारा 'श्रेय' मुझको जाता है। जैसे कि दूसरी पार्टी के एक नेता ने हमारे एक कॉमरेड से कहा, ''ऐसा मत कहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह आदमी कुछ कैडरों का निर्माण कर रहा है, जबकि मैं कैडरों की गुणवत्ता के बारे में काफी हैरान परेशान हूँ जिनका हम निर्माण कर रहे हैं।'' दूसरे प्रशंसा में जो चाहे कह सकते हैं। मैं अपने कैडरों को उचित स्तर का नहीं पाता हूँ। कैडरों की बातें सुनकर आजकल में क्षुब्ध हो जाता हूँ। जो कुछ वे कहते हैं अक्सर उसके सिर-पैर का पता मैं नहीं लगा पाता हूँ। यहाँ तक कि नेतृत्वकारी कॉमरेड भी एक बिन्दु को स्पष्ट करने के प्रयास में इसे और भी जटिल बना देते हैं। शायद एक बिन्दु जो कुछ दूर तक स्पष्ट था लेकिन उसे और भी स्पष्ट करने के प्रयास में वे इसे धुंधला बना देते हैं। हमें मुद्दे को स्पष्ट करने, भ्रान्ति दूर करने और कुछ रोशनी डालने के लिए सुस्पष्ट बात रखनी चाहिए। हमें मुद्दे को सूक्ष्मता और सुस्पष्टता से रखना चाहिए ताकि यह लोगों को आकर्षित कर सके और उनके दिमागों में पैठ जाए। लेकिन अपने गहन ज्ञान को प्रदर्शित करते हुए हम बहुत बोलते हैं और उस जरूरी बात को भूल जाते हैं जिसे हमको बताना चाहिए था। हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी किस्म के कॉमरेड भी हैं जो सभाओं में बेकार चीजों के बारे में बहुत बोलते हैं, जो मात्र अपने ज्ञान का दिखावा करते हैं और विश्व राजनीति के बारे में सब कुछ चर्चा करते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य से भटक जाते हैं। यह सब सुनकर मैं बेचैन हो जाता हूँ। कुछ पुराने अनुभवी कॉमरेड भी हैं जो नहीं जानते कि प्रभावशाली ढंग से कैसे बोला जाए, एक बिन्दु को कैसे सामने लाया जाए। दूसरों के तर्कों को सुनने के बाद कैसे एक बिन्दु को पेश किया जाए। उन्होंने यह सब नहीं सीखा है। (शेष अगले अंक में)

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly, Date of Printing : 5 April, 2015

रेलवे प्लेटफार्म टिकट रेट दुगुना करने का विरोध

प्रधानमंत्री का पुतला फूंकते हुए एसयूसीआई (सी) कार्यकर्ता

पटना : रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को 5 से बढ़ाकर 10 रुपये किये जाने तथा रेल मालभाड़े में वृद्धि के खिलाफ 1 अप्रैल को पटना जंक्शन गोलम्बर पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पटना जिला कमिटी के तत्वावधान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला दहन किया गया। फिर वहां एक सभा आयोजित की गयी। मौके पर उपस्थित एसयूसीआई (सी) कार्यकर्ता बीजेपी-नीत केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगा रहे थे।

सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भाजपा ने अपने आम बजट में इस बात का संकेत दिया था कि बजट के बाहर भी टैक्स में बढ़ोतरी की जा सकती है। सरकार द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये करना आम जनता पर इस दिशा में पहला प्रहार है। इतना ही नहीं, मंडल रेल प्रबंधकों को मेलों, रैलियों आदि मौकों पर प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करने की आड़ में प्लेटफॉर्म टिकट की दर में और बढ़ोतरी करने का अधिकार दिया गया है। वक्ताओं ने सरकार के इस जुल्मी फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अपने सगे-संबंधियों को स्टेशन छोड़ने और स्टेशन से लेने वाली आम जनता पर बोझ और बढ़ेगा। साथ ही वक्ताओं ने यूरिया, कोयला, सीमेंट और एलपीजी जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं के माल भाड़े में क्रमशः 10, 6.3, 2.7 तथा 0.8 फीसदी की बढ़ोतरी की कड़ी भर्त्सना की और कहा कि इससे पहले से ही महंगाई से त्रस्त देश की जनता और बेहाल होगी। वक्ताओं ने लोक निजी भागीदारी की आड़ में रेलवे में निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने की भी कड़ी भर्त्सना की। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में प्लेटफॉर्म टिकट की दर में की गयी वृद्धि तथा माल भाड़े में वृद्धि को अविलम्ब वापस लेने की मांग की।

सभा को पटना जिला कमिटी के वरिष्ठ सदस्य मणिकांत पाठक, सूर्यकर जितेन्द्र, अनामिका, अनिल कुमार आदि ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता राजकुमार चौधरी ने की।

मुजफ्फरपुरः 1अप्रैल को एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) की ओर से रेलवे प्लेटफार्म टिकट का मूल्य 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रु करने एवं भोजन उत्पादों के मूल्य वृद्धि के खिलाफ मोतीझील स्थित पार्टी कार्यालय से मुजफ्फरपुर जंक्शन तक जुलूस निकाला गया एवं रेलमंत्री का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के बाद सभी की गई।

सभा को सम्बोधित करने वालों में एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) के जिला सचिव अर्जुन कुमार,राज्य कमेटी सदस्य लालबाबू महतो, काशीनाथ सहनी, कालीकांत झा, बिपिन ठाकुर, आशुतोष कुमार, लालबाबू राय, मो. इदरीश, वैद्यनाथ पण्डित आदि प्रमुख थे।

एक नजर में बीजेपी सरकार का केन्द्रीय बजट

पूँजीपतियों को क्या मिला?

1. पूँजीपतियों का देय टैक्स 5 प्रतिशत घटाया। पहले देना पड़ता था 30 प्रतिशत , अब देना पड़ेगा 25 प्रतिशत।

2. पूँजीपतियों की टैक्स छूट की मात्रा बढ़ाई। वर्ष 2013-14 में कारपोरेट क्षेत्र को 57, 793 करोड़ रुपये की टैक्स छूट दी गई थी, चालू आर्थिक वर्ष में छूट दी गई है 62,398 करोड़ रुपये।

3. सम्पत्ति कर हटा दिया गया है। वे चाहे कितनी ही सम्पत्ति के मालिक हों उन्हें कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

4. निजीकरण का दरवाजा खोल दिया गया है। 12 बड़े-बड़े बंदरगाहों को निजी हाथों के हवाले कर दिया जाएगा। राष्ट्रीकृत संस्था के शेयर बेचे जा रहे हैं।

आम आदमी को क्या मिला?

1. रेल बजट में माल भाड़ा 2 से 10 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए तमाम चीजों के दाम बढ़ेंगे।

2. कोयले पर सैस दुगुना कर दिया है।

3. सर्विस टैक्स 12.34 प्रतिशत से बढ़ा कर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे महंगाई और भी बढ़ेगी।

4. शिक्षा खर्च के लिए आवंटन घटा दिया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता के मद में पिछले साल का बजट आवंटन था 51,828 करोड़ रुपये। इस बार घटा कर कर दिया गया है 39,038.50 करोड़ रुपये। उच्च शिक्षा में भी बजट आवंटन लगभग 1000 करोड़ रुपये घटा दिया गया है।

5. स्वास्थ्य बजट भी घटा दिया गया है।पिछले साल बजट आवंटन था 35,163 करोड़ रुपये, जबकि इस बार घटा कर उसे 33,152 करोड़ रुपये कर दिया गया है। स्वास्थ्य बीमा पर जोर दिया गया है, जिसका मायने है स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी से सरकार अपना पल्ला झाड़ कर निजी हाथों में सौंप देना चाहती है।

6. ग्राम विकास में बजट आवंटन में भारी कटौती कर दी है। वर्ष 2013-14 में ग्राम उन्नयन के लिए बजट आवंटन था 51,757 करोड़ रुपये। इस बार 10 प्रतिशत घटा दिया गया है।

7. इन्दिरा आवास योजना में 8,200 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है।

8. कृषि में वर्ष 2013-14 में योजना खर्च में आवंटन था 17,788 करोड़ रुपये। इस बार आंटन है 11,657 करोड़ रुपये।

9. सिंचाई के लिए बजट आवंटन वर्ष 2013-14 में 1757 करोड़ रुपये था। इस बार 772 करोड़ रुपये कम हो गया है।

10 महिला और बाल कल्याण मद में बजट आवंटन में 56 प्रतिशत कटौती कर दी गई है। आईसीडीएस स्कीम में पिछले साल बजट आवंटन था 18,108 करोड़ रुपये। इस बार कर दिया गया है 8,245 करोड़ रुपये।

11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के मद में बजट आवंटन में 20 हजार करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है।

देश ने क्रान्तिकारियों को ....

(पृष्ठ 5 का शेष)

छोटी गैबी, माधोपुर, निराला नगर आदि विभिन्न मुहल्लों के लगभग 15 स्थानों पर पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद शहीद उद्यान पार्क सिगरा से छात्र-नौजवानों नारे लगाते हुए एक रैली निकाली जो सिगरा चौराहा, साजन तिराहा होते हुए पुनः शहीद उद्यान पार्क में आकर समाप्त हो गयी। विभिन्न मुहल्लों के लोगों ने भगत सिंह की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की और उनके विचारों से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व कमलेश मौर्य, प्रेम प्रकाश पटेल, सुरेन्द्र प्रसाद, प्रवीण यादव, विकास कुमार, अजीत कुमार, आकाश आदि ने किया। छोटी गैबी में शाम को कैंडिल जलाकर नौजवानों नें शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट की।

25 मार्च को पराड़कर स्मृति भवन, मैदागिन, वाराणसी के सभागार में ऑल इण्डिया डीवाईओ के द्वारा महान क्रान्तिकारी शहीद-ए-आज़म भगतसिंह, सुखदेव एवं राजगुरु शहादत दिवस समारोह चन्द्रेश कुमार के उद्बोधन के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री प्रेम प्रकाश पटेल ने की एवं संचालन श्री कमलेश मौर्य ने किया। आशू ठाकुर नें एक क्रान्तिकारी गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ए.आई.डी.वाई.ओ. के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉ. दीपक कुमार थे। अन्य वक्ताओं में भारतीय शिशु मन्दिर के प्रधानाचार्य श्री प्रहलाद यादव, बंगाली टोला इ. का. के अवकाशप्राप्त प्रधानाचार्य श्री आर.पी. चौरसिया, सी.पी.आई.(एमएल) के उ.प्र. राज्य सचिव कॉ. बचाऊराम, ए.आई.डी.वाई.ओ. की उ.प्र. राज्य कमेटी के कोषाध्यक्ष कॉ. प्रमोद कुमार शुक्ल, श्री रामकृष्ण विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज के शिक्षक सुरेन्द्र प्रसाद आदि प्रमुख थे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बुद्धिजीवी, महिलाएँ, छात्र एवं नौजवान शामिल हुए।

जमशेदपुर

सोनीपत (हरियाणा) : ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. की तरफ से हिन्दू कॉलेज में शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शहादी दिवस कार्यक्रम में छात्रों ने रागनी, गाने और कविताएं सुनाई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति के सदस्य ईश्वर दहिया थे। मंच संचालन ए.आई.डी.एस.ओ. के जिला सचिव प्रवीण नाहरा ने किया। कॉलेज के हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. बी.के. गर्ग ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

दुर्ग (छत्तीसगढ़) : 23 मार्च को एआईडीएसओ की दुर्ग इकाई द्वारा महान क्रांतिकारी शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के 84वें शहादत दिवस के अवसर पर शहीद चौक पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, चन्द्रशेखर आजाद की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात एआईडीएसओ के कार्यकर्ता साइन्स कॉलेज दुर्ग पहुँचे और कॉलेज गेट पर भगत सिंह की फोटो पर पूरे सम्मान के साथ माल्यार्पण कर सभा की।

पिलानी (राजस्थान) में भी 23 मार्च को एआईडीएसओ-एआईडीवाईओ द्वारा इन क्रान्तिकारी शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भद्रक में ऑटोनॉमस कॉलेज में शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहीदी दिवस के अवसर पर 19 से 24 मार्च तक क्रिकेट टुर्नामेंट आयोजित किये गये।

सागर (म.प्र.)

"Print-line
Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."